लॉलीपॉप चप्पू से होगी चुनावी वैतरणी पार या भाजपा नैया डूबेगी मझधार

फ़रीदाबाद (म.मो.) भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मंत्रणा के दौर चल रहे हैं। तभी सूरजकुंड में तो कभी सेक्टर 12 के 'हूडा' कन्वेंशन सेंटर में। झकाझक सफ़ेद कलफ़दार कुर्ते पाजामे और गले में भाजपाई पटके तमाम छोटे-बड़े नेताओं के माथे पर उभरी चिंता की लकीरों को छिपा नहीं पा रहे थे।

चिन्ता इस बात की नहीं कि स्कूलों व शिक्षकों के अभाव में हरियाणा के आधे से अधिक बच्चे पढ़ नहीं पा रहे; इस बात की भी नहीं कि अस्पतालों व डॉक्टरों के अभाव में जनता बेमौत मर रही है। बिजली, पानी, बेरोजगारी व महंगाई को तो भाजपा सरकार समस्या मानती ही नहीं।

माथे पर चिंता की लकीरें केवल इस बात पर हैं कि लूट व गुंडागर्दी का जो पटा इन्हें 5 साल के लिये मिला था और जिसे ये लोग सारी उम्र के लिये मान कर चल रहे थे, अब समाप्त होने के कगार पर है। इसके नवीनीकरण की कोई सम्भावना नज़र नहीं आ रही।

चार वर्ष तक जनता को लूटने के बाद अब जनता को नया लॉलीपॉप दिया है। 'आयुष्मान भारत' का। इसके अनुसार देश के 50 करोड़ सबसे ग़रीब लोग़ों का स्वास्थ्य बीमा करके इलाज किया जायेगा। विदित है कि बीमारों का इलाज करने के लिये डॉक्टरों व अस्पतालों की जरूरत होती है न कि बीमा कम्पनियों की।

भाजपा सरकार ने बीते 4 वर्ष में डॉक्टरों व अस्पतालों की कमी को दूर करने के लिये कोई कदम नहीं उठाये, यहां तक कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किये गये अधूरे कामों को पूरा करने की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) द्वारा अलवर व अन्य शहरों में बने चार मेडिकल कॉलेजों की इमारतों में उल्लू बोल रहे हैं। सैंकड़ों-सैंकड़ों करोड़ की बनी खड़ी बिल्डिंगे दिनों-दिन जर्जर होती जा रही हैं; किसी को कोई चिंता नहीं। अब 'आयुष्मान भारत' के तहत बीमा कम्पनियां, वे भी निजी देशी-विदेशी, किसका कितना इलाज कर पायेंगी, इसे देशवासी बखूबी समझते हैं।

एक और ताज़ातरीन लॉलीपॉप आत्महत्या करते किसानों को दिया है। वैसे 2014 के चुनाव पूर्व रैलियों में मोदीजी स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशें सत्ता में आते ही तुरंत लागू करने की बात करते थे। लेकिन सत्तारुढ़ होते ही 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का राग अलापने लगे। लेकिन अब सत्ता हाथ से फ़िसलती नज़र आने लगी तो 2022 को भूल कर तमाम फ़सलों का समर्थन मूल्य बढाने की घोषणा यकायक कर दी।

गोदी मीडिया द्वारा इस बढौतरी को ऐतिहासिक बता कर खूब ढोल पीटा जा रहा है। इसे किसानों के लिये बेहद लाभकारी संजीवनी बूटी बताया जा रहा है जिससे किसानों के सारे दुख दर्द दूर हो जायेंगे। इस नकली संजीवनी से भाजपाई नेता ही खुश हो सकते हैं। बिल्ली को देखकर कबूतर द्वारा आंख मींचने की तर्ज पर भाजपाई आगामी चुनावी वैतरणी पार करने का धोखा तो पाल सकते हैं; परन्तु धरातल की कड़ी परिस्थितियों को झेल रहा किसान हर रोज़ मंडी में देखता है कि सरकार के संरक्षण में व्यापारी व सरकारी कर्मचारी उसे कैसे लूट रहे हैं।

लॉलीपॉप जुमलेबाज़ी की नाव में सवार होकर एक बार सत्ता तक पहुंच चुके भाजपाइयों को यह बड़ा भारी वहम है कि इस बार भी वे उसी तरह पुन: सत्ता हथिया लेंगे। लेकिन कहावत है कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ा करती। बीते चार सालों में जनता ने खूब देख लिया कि 100 दिन में देश का काला धन लाकर हर नागरिक को 15-15 लाख देने का क्या हुआ, 100 दिन में महंगाई घटाने का क्या हुआ, हर साल करोड़ों रोज़गार देने का क्या हुआ, रुपये को डॉलर से मजबूत करने व पैट्रोलियम के बढ़ते दामों का क्या हुआ?

जनता गोदी मीडिया एवं प्रचारतंत्र के बहकावे में आने की अपेक्षा अपने सामने खड़ी हर सच्चाई को ज़्यादा बेहतर पहचानती है। भाजपा की मंत्रणा कही यंत्रणा न साबित हो।

कंपनियों के मुनाफ़े के आगे बच्चों के स्वास्थ्य की भी चिन्ता नहीं अमेरिका को

सालों के शोध के बाद डॉक्टरों ने ये पाया है कि नवजात शिशु के लिये मां का दूध सबसे अच्छा ही नहीं बल्कि जरूरी है। पहले छ: महीने में अगर बच्चा मां का दूध पिये तो उसकी रोगों से लड़ने की ताक़त बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो आसानी से बीमार भी नहीं होता। इसके अलावा पहले छ: महीनों में मां का दूध ही बच्चे के लिये सम्पूर्ण और प्रर्याप्त आहार है। यानी कि उसको और कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि अलग से पानी पीने की भी जरूरत नहीं है।

पिछले दिनों जिनेवा में हुई, विश्व स्वास्थ्य सभा (वर्ल्ड हैल्थ एसेम्बली) की एक बैठक में इक्वाडोर राज्य ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रखा था। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत आता है। सैंकड़ों देशों के प्रतिनिधि इस प्रस्ताव के समर्थन में थे और इसलिये ये उम्मीद थी कि प्रस्ताव आसानी से और तुरंत पास हो जायेगा। लेकिन सभी की हैरानी और दुख की सीमा ना रही-जब अमेरिका ने इक्वाडोर और उसके बाद कई अन्य छोटे देशों को डरा धमका कर यह प्रस्ताव पेश करने से रोक दिया।

बताया जाता है कि अमेरिकी कंपनियों द्वारा लगभग 70 अरब डॉलर (लगभग 4800 अरब रुपये) का कृत्रिम शिशु दूध हर साल पूरे विश्व में बेचा जाता है। इस प्रस्ताव से इन कंपनियों का दूध का ये गैर जरूरी कारोबार ठप्प हो जाता। इसलिये अमरीका ने विश्व के (और अपने देश के भी) बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता किये बग़ैर अपनी कंपनियों का मुनाफ़ा बचाना ज़्यादा जरूरी समझा। उसकी बला से बच्चे बीमार रहें या मरें।

प्रस्ताव में सिर्फ़ इतना कहा गया था कि विश्व के सभी देशों की सरकारें मां द्वारा अपने बच्चे को स्तनपान कराने को समर्थन और बढावा देंगी और इसका प्रचार व सुरक्षा करेंगी। इस प्रस्ताव में कृत्रिम शिशु दूध के उपयोग को बढावा न दिया जाये, ऐसे कदम उठाने को भी सरकारों से कहा गया था। जाहिर है इन कदमों से नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा होती लेकिन अमेरिका की कंपनियों का मुनाफ़ा कम हो जाता।

अमेरिका ने प्रस्ताव को पेश होने से रोकने के लिये संयुक्त राष्ट्र को दी जाने वाली अपनी मदद को भी बन्द करने की धमकी दी थी। लेकिन सब धमकियों के बावजूद रूस द्वारा प्रस्ताव पेश कर दिया गया। जिसको अमेरिका धमकाने का साहस नहीं कर सका। ध्यान रहे कि पिछले 70 सालों के शोध और तजुर्बे के बाद विश्व के वैज्ञानिक और डॉक्टर एकमत से इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पहले छ: महीने शिशु को मां का दूध ही पिलाया जाना चाहिये और कुछ भी नहीं। यही उसके लिये सर्वोत्तम है और सम्पूर्ण आहार है।

-अजातशत्रु

नौकरी के नाम पर बेरोज़गारों की जेब काटने का यह कैसा लॉजिक है

किसी भी सरकारी विभाग की रिक्तियां निकलती हैं तो उसकी फार्म फीस 500-700 होती ही हैं। सरकार बेरोजगारो से पैसा कमाना चाहती हैं या उन्हें रोजगार देना ??? अभी तक पता नहीं चला है ।

उदाहरण के लिए- पोस्ट होती हैं 50 फॉर्म पूरे भारत से भरवाते हैं । फॉर्म फीस होती है 500 रु। 50 लाख से 80 लाख बेरोजगारों फॉर्म भरते हैं। आइये सरकार का फायदा देखते हैं।

500 रु फॉर्म फीस में 50,00,000 बेरोजगारों ने फॉर्म भरें = (कुल आय फॉर्म फीस से) 2 अरब 50 करोड़ रु। नौकरी देनी हैं 50। सैलेरी 25000 रु प्रति माह मान लेते हैं। ज्यादा मानी गयी हैं इतनी होती नहीं हैं।

25000 में 50 लोग = 12,50,000 महीना। 12,50,000 में 12 महीने = 1 करोड़ 50 लाख। चालीस साल की नौकरी करने पर- 1,50,00,000 में 40 साल = 60 करोड़। सरकार की फॉर्म फीस कुल आय = 2 अरब 50 करोड़ रूपए। अप्पोइंटेड लोगों की 40 साल तक की सैलेरी- 60 करोड़ रु। 2,50,00,00,000 - 60,00,00,000 = 1,90,00,00,000। यानी सरकार की कुल आय = 1 अरब 90 करोड़ रु।

सवाल सरकार से यह है कि आप बेरोजगारों को नौकरी देना चाहते हैं या उनकी जेब काट कर पैसा कमाना चाहते हैं ???

प्रिंसिपल भगवती के संरक्षण में छात्राओं से छेड़खानी करता कर्मचारी

सै.16 ए फ़रीदाबाद स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने नाम न छापने की शर्त पर इस संवाददाता को बताया कि भारत नामक एक कर्मचारी उनके साथ बहुत बद्तमीजी करता है। एक छात्रा ने तो यह भी बताया कि वह उसका पीछा करते-करते उसके घर तक भी पहुंच गया। बदनामी के डर से घर वालों ने पुलिस में शिकायत नहीं की। यह कर्मचारी वैसे तो ठेकेदारी में है पर बैठा रहता है लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है कि प्रत्येक छात्रा को काम पड़ता है। यह कर्मचारी मौके का लाभ उठाकर छात्राओं से छेड़खानी व बद्तमीजी करने से बाज नहीं आता।

छात्राओं ने इस बाबत कई बार प्रिंसिपल भगवती राजपूत को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर इसकी शिकायत की है, जब कोई असर नहीं हुआ तो छात्राओं ने शिकायत पेटिका में अपनी शिकायतें डाल दी। जिन्हें दौरे पर आये डिप्टी डायरेक्टर महोदय ने स्वयं पढकर प्रिंसिपल को उचित कार्यवाही करने के आदेश दिये। परन्तु इसके बावजूद प्रिंसिपल ने अपने इस चहेते लोफ़र कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। इसके चलते इस कर्मचारी के हौंसले और भी बुलंद हो गये हैं और इसकी बेजा हरकतें बढ़ती जा रही हैं।

हवा-हवाई कॉलेज चलाना चाहती है सरकार

फ़रीदाबाद (अजातशत्रु) पिछले अंक में आप पढ चुके हैं कि किस तरह बिना किसी भवन एवं स्टाफ़ के सरकार दनादन नये कालेज खोलती जा रही है। गौरतलब है कि खट्टर सरकार ने इसी सत्र से 31 महिला कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। उनके लिये जबरदस्ती छात्रायें भर्ती भी कर ली हैं। जबरदस्ती इसलिये कि इन नये कॉलेजों का कहीं अता-पता ही नहीं ना भवन ना अध्यापक और दाखिलों के लिये पूरा दबाव। ऐसे में जाहिर है कोई भी छात्रा इन कॉलेजों में दाखिला लेने को तैयार नहीं थी। लेकिन क्योंकि खट्टर और मोदी अपनी पीठ खुद ही थपथपाना चाहते थे इसलिये जबरदस्ती इन कॉलेजों में भर्ती की गई ये झूठा आश्वासन देकर कि दाखिला उनका बेशक नये कॉलेज के नाम पर है पढाई पुराने कॉलेजों में ही होगी।

दूसरी दिक्कत यह है कि जुमलेबाजों ने तो सिर्फ़ घोषणा करके अपना भोंपू बजाना था इसलिये बजट का कोई इन्तजाम नहीं। ना इनके नये भवन बनाने का ना नये अध्यापक भर्ती करने का। इसके अलावा कॉलेजों में एक और फंड से पैसा आता है वह है 'उच्चतर शिक्षा अभियान'। लेकिन इस फंड से भी नये कॉलेजों को कोई पैसा नहीं मिलने वाला। इसलिये अगले एक दो सालों में ना तो इन नये कॉलेजों के भवन बनने की उम्मीद हैऔर ना ही अध्यापकों की। बस एडमिशन को लेकर चाटो।

जहां तक प्राध्यापकों का सवाल है पूरे राज्य में कोई कॉलेज ऐसा नहीं जहां पूरे अध्यापक हों। नेहरू कॉलेज फ़रीदाबाद में कुल प्राध्यापक के 140 पद हैं जिनमें से सिर्फ़ 60 प्राध्यापक नियुक्त हैं बाकी दिहाड़ीदारों से काम चलाया जाता है जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसी तरह महिला महाविद्यालय में लगभग 40 नियमित पद हैं जिनमें से 20 पद खाली पड़े हैं। **जब पहले से चल रहे कॉलेजों में ही पढ़ाने को टीचर नहीं है तो नयों में कहां से आयेंगे? इसका एक बड़ा ही तुगलकी हल निकाला है उपर बैठे सरकार के प्यादों ने -वह है 'डेपुटेशन। इसमें एक प्राध्यापक तीन दिन एक कॉलेज में पढायेगा और तीन दिन दूसरे में। यानी कि तीन दिन फ़रीदाबाद तो तीन दिन होडल-और इसके लिये उसे कोई किराया भाड़ा भी सरकार नहीं देगी। यानी वह होगा धोबी का कुत्ता-घर का न घाट का, लेकिन बोझा दूना। आश्चर्य यह है कि इतना शोषण होने के बावजूद इस अन्यायपूर्ण और मूर्खतापूर्ण नियम के खिलाफ़ ना तो अभी तक किसी प्राध्यापक ने आवाज उठायी है और ना ही उनकी यूनियन ने।**

एक और मजेदार बात ये है कि इन नये कॉलेजों में सरकार के 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' के तहत भी पैसा नहीं मिलने जा रहा। क्योंकि इस स्कीम में पहले से बने हुये भवन की मरम्मत के लिये ही पैसा आता है। और उसमें भी महिला कॉलेजों को प्रथमिकता। इसी कारण सै. 16 ए फ़रीदाबाद के महिला कॉलेज के लिये तो अनाप-शनाप पैसा आ रहा हैलेकिन साथ ही बसे नेहरू कॉलेज या तिगांव कॉलेज के लिये नहीं। जबकि तिगांव कॉलेज में तो चारदिवारी तक नहीं है जिससे कोई भी गुंडा कहीं से भी कॉलेज में घुसकर लड़कियों को छेड़ जाता है।

अब इन मूर्खाधिराजों अफ़सरों ओर उनके तुगलक बादशाह खट्टर से पूछो कि लड़कियां क्या सिर्फ़ महिला कॉलेजों में ही पढती है। दूसरे कॉलेजों में लड़कों के साथ पढ़ने वाली लड़कियां क्या लड़कियां नहीं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उन कॉलेजों में भवन व चारदीवारी बनाने की कोई जरूरत नहीं और सौ बातों की एक बात तो ये है कि जब पढाने को कोई अध्यापक ही नहीं तो नये कॉलेजों और भवनों को क्या छात्रायें चाटेंगी?

इधर अभी-अभी प्रधान जुमलेबाज श्रीमान मोदीजी ने एक और शुरूआत की है। 'उत्कृष्ट संस्थान योजना' यानी कि 'इन्स्टीच्यूट ऑफ़ इमीनेंस'। क्योंकि सारे कॉलेज और विश्वविद्यालयों को तो चलाना बस का था नहीं क्योंकि उस पर पैसे खर्च होते हैं और पैसे अदानी, अम्बानी के अलावा वो किसी पर खर्च करना नहीं चाहते, इसलिये पिछले दिनों सरकार ने ये तय किया कि वो 20 सबसे अच्छे (10 सरकारी और 10 निजी) शिक्षा संस्थानों को देश भर से छांट कर उन्हें 1000 करोड़ रुपये पांच साल में देगी ताकि वो पूरे विश्व में अपना स्थान बना सकें। अब उसके लिये सरकार ने 6 संस्थानों की घोषणा की है 3 सरकारी (जिनमें 2 आइ.आइ.टी) ही है। और तीन प्राईवेट 1 इन 3 प्राइवेटों में एक अम्बानी का जियो इन्टस्ट्यूट है जिसका हाल हरियाणा के नये खुले महिला कॉलेजों जैसा है-ना भवन ना अध्यापक, और वहां तो छात्र भी नहीं। और इस पर मोदीजी लुटायेंगे हमारे खून पसीने की कमाई का 1000 करोड़ रुपये। यानी अम्बानी को एक पैसा लगाने की जरूरत नहीं। पैसा हमारा नाम उसका और मोदी को बताओ ईमानदार। और भ्रष्टाचार कैसे होता है भाई? लोगों को लाख पूछने पर भी सरकार अभी तक ये नहीं बता पायी है कि जब एक संस्थान चालू ही नहीं हुआ तो सरकार ने ये कैसे तय किया कि वो उत्कृष्ट है और उसे इस सूची में शामिल किया जाये। शायद सरकार को मुहावरा याद आ गया होगा कि-पूत के पांव पालने में ही दिखायी दे जाते हैं।

इसके अलावा एक नया काम इस साल से ये किया है कि सभी कॉलेजों में सारे दाखिले ऑन-लाइन होंगे। अब वही बात है कि गधी मरी पड़ी है भाड़े लाहौर के। बिजली छ:-छ: घंटे गुल रहती है। लैपटॉप या कम्पयूटर तो दूर ज्यादातर छात्रों के पास स्मार्ट फ़ोन तक नहीं है। फ़िर भी आप इसको अमेरिका बनाना चाहते हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि ज़्यादातर छात्रों को साईबर कैफ़े वालों के पास लुटना पड़ा है। 300 से 400 रुपये देकर एक-एक छात्र ने वहां से फ़ार्म भरवाया है वो भी गलत। उसको चैक करने के लिये मास्टरों की कवायद अलग। उसके बाद भी ज़्यादातर छात्रों को पूरा कार्यक्रम ठीक पता नहीं होने की वजह से कई अच्छे छात्र तय तारीख तक फ़ीस भरने के लिये नहीं आ सकें और वो एडमिशन से वंचित रह गये। मतलब अफ़सरों ने वाहवाही लूटने के लिये कितने छात्रों का भविष्य बर्वाद कर दिया।

कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति बड़ी चिंताजनक है। सरकारी स्कूल बन्द किये जा रहे हैंऔर सरकारी कॉलेज दनादन खोले जा रहे हैं, लेकिन उन के लिये कोई टीचर नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई स्टाफ़ नहीं और कोई वजह नहीं। सिर्फ़ घोषणा है, ढिंढोरा पीटना है और छात्रों अध्यापकों को तुगलकी फ़रमानों से दुखी रखना है। फ़िर भी चुनाव के वक्त जातिवाद और धर्म का जहर फ़ैलाकर ऐसे जनता के दुश्मन चुनाव जीतकर आते हैं तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और युवाओं को इस पर सोचने की जरूरत है।